विरोध पत्र

13 फरवरी 2016

श्री मनोहर लाल खट्टर,

मुख्यमंत्री, हरियाणा

विषय– किसानों की दुर्दशा, कमरतोड़ महंगाई, पेट्रोल डीजल की मुनाफाखोरी, झूठे वायदे, बिजली के अनाप–शनाप बिलों तथा महंगी दरों के विरोध में विशेषतः जीन्द तथा पूरे हरियाणा की जनता का विरोध पत्र ।

आदरणीय महोदय,

1 किसानों पर दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे अत्याचार :–

भाजपा सरकार की कुनीतियों से त्रस्त समूचा किसान वर्ग हताश व मजबूर है। **"खट्टर व नरेंद्र मोदी– दोनों हैं किसान विरोधी"** का नारा आज गांव गांव में हर बड़े और बच्चे की जुबान पर है।

भाजपा सरकार किसानों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार व जुल्म ढ़ा रही हैं । आपकी सरकार ने किसान की हर फसल जैसे धान, कपास, बाजरा, ज्वार, आलू या पोपुलर– सफेदा आदि को उचित बाजार भाव के अभाव में पूरी तरह से फेल कर दिया है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था जिसके अनुसार प्रत्येक फसल की लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ भाव तय करना था। लेकिन गद्दी पर बैठते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा सरकार ने अपने इस वायदे को पूरी तरह से नकार दिया।

कपास की फसल पर सफेद मक्खी से हुए नुकसान की उचित गिरदावरी न करना और ना ही मुआवजा दिया जाने से पीड़ित किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। गेहूं का **'अनुपचारित बीज'** हरियाणा सरकार द्वारा किसान को बांट दिया जाना अपने आप में एक बहुत **बड़ा घोटाला** है, जिसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है।

आज तक भी लगभग **'5000 करोड़ रु. के धान घोटाले'** की जांच न तो हरियाणा सरकार पूरी करवा पाई है और न ही दोषियों को चिन्हित किया गया है।

पिछले वर्ष तो हरियाणा का किसान पुलिस थानों में खाद की लाईनों में अपमानित किया गया, तो इस वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा किसानों से 'जे' फार्म लेकर उसके बदले कूपन द्वारा ईनाम दिए जाने की घोषणा किया जाना परंतु एकबार फिर न कूपन व न ईनाम देकर किसान को दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

सच तो यह है कि हरियाणा व देश का किसान मोदी सरकार व हरियाणा सरकार की बेरुखी के चलते अपने आप को ठगा और लुटा महसूस करता है।

2. कमरतोड़ महंगाई व पेट्रोल–डीजल की मुनाफाखोरी :–

हरियाणा का आम जनमानस, छोटा दुकानदार, व्यापारी व कर्मचारी चौतरफी महंगाई की मार से पीड़ित है। एक तरफ दाल की कीमतें आज भी 170 रु. से 200 रु. किलो के बीच में हैं, तो खाने का तेल 160 रु. लीटर है। अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं।

दूसरी तरफ मोदी सरकार तथा हरियाणा सरकार मिलकर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर एक्साईज ड्यूटी व सेल्स टैक्स के माध्यम से जनता को लूट अपना खजाना भरने में लगी हैं। सच तो यह है कि दोनों सरकारें **"मुनाफाखोरों की दुकान"** बन गई हैं।

जब भाजपा सरकार ने 26 मई, 2014 को देश की सत्ता सम्हाली, तो कच्चे तेल का भाव 108.05 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल था। यह आज घटकर लगभग 30 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है। **कच्चे तेल** की कीमतों में लगभग **20 महीने में 72.21 प्रतिशत गिरावट** आई है। अगर यह आंकड़ा लें और आम जनमानस को कच्चे तेल की कम हुई कीमतों का लाभ दें, तो आज की तारीख में **पेट्रोल का भाव** हरियाणा में रु. 60.22 प्रति लीटर की बजाए **रु. 19.40 प्रति लीटर** होना चाहिए। इसी प्रकार **डीजल की कीमत** हरियाणा में रु. 44.68 प्रतिलीटर की बजाए **रु. 15.71 प्रति लीटर** होनी चाहिए। मोदी सरकार ने डीजल–पेट्रोल पर 19 महीने में 10 बार एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर तथा हरियाणा सरकार ने 15 महीने में 2 बार सेल्स टैक्स बढ़ाकर मुनाफाखोरी की एक नई मिसाल पेश की है। आज पूरे देश में केवल पेट्रोल–डीजल पर लगाए गए करों से सरकार दो लाख करोड़ का मुनाफा कमा रही है। क्या यह न्यायोचित है?

इन कुनीतियों के चलते दुकानदारी व व्यापार पूरी तरह से ठप्प है। साधारण दुकानदार यह कहने पर मजबूर है– **"उद्योग ठप्प– ठंडा व्यापार, ऐसी रही खट्टर सरकार"**।

3. झूठे वायदे–टूटे वायदेः–

हरियाणा की भाजपा सरकार **"झूठे वायदों–टूटे वायदों"** की एक अजब दास्तान बन गई है। खट्टर सरकार के बारे में आम जनमानस का मानना है– **"सरकार चलाना नहीं आता– कोरा है बही खाता"।**

सत्ता में आने से पहले नौजवानों, किसानों, वृद्धों, कर्मचारियों, व्यापारियों आदि वर्गों से किए सैकड़ों वायदों में से सरकार एक भी पूरा नहीं कर पाई है। सभी वर्ग खट्टर सरकार की नाकामयाबी और नातजुर्बेकारी से अत्यंत पीड़ित है।

हरियाणा का नौजवान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। खट्टर सरकार ने हर 12 वीं पास नौजवान को रु. 6000 प्रतिमाह व बीए पास नौजवान को रुपया 9000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था। परंतु आज तक किसी नौजवान को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। उल्टा डेली वेज व एडहॉक पर काम करने वाले लगभग 40,000 से अधिक व लगभग 11,000 गेस्ट तथा कंप्यूटर अध्यापकों की नौकरी निकाल उनकी रोटी व रोजगार पर कुठाराघात किया गया है। लाखों नौजवानों को रोजगार का वायदा देने वाली खट्टर सरकार ने 15 महीने में एक नौजवान को भी रोजगार नहीं दिया।

4. बिजली बिलों के विरुद्ध हाहाकारः–

हरियाणा प्रांत में चारों तरफ बिजली बिलों के विरुद्ध हाहाकार मचा है। गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों के बिजली बिलों में भाजपा सरकार द्वारा 40–50 प्रतिशत की बेइंतहाशा वृद्धि की गई है। लगभग यही हाल दुकानदारों, छोटे वाणिज्यिक संस्थानों व लघु उद्योगों का भी है, जो भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

भाजपा ने छोटे से छोटे घर में रहने वाले साधारण व्यक्ति का बिजली बिल प्रतिमाह रुपया 6,000 से रुपया 10,000 रूपए तक कर दिया है । मध्यम वर्गीय परिवारों का बिजली बिल तो रुपया 15,000 से रुपया 20,000 तक आ रहा है। दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और लघु उद्योगों की स्थिति तो और भी बदतर है।

बिजली कंपनियों के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हरियाणा की जनता, खासतौर से शहरों में रहने वाले लोग, भाजपा की सरकार का गठन करके अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।

बिजली की छापेमारी

सबसे मुश्किल बात तो यह है कि भाजपा सरकार में बिजली कर्मचारियों द्वारा घरों पर **'बिजली की छापेमारी'** अब रोजमर्रा की बात हो गई है। जनता खौफ के साये में जी रही है कि कब बिजली विभाग के अधिकारी छापेमार दस्ते के सहित घर पर हमलावरों की तरह पहुंच जाएंगे। दुर्भाग्य से शायद ही कोई मोहल्ला या गली इस बिजली के छापामारी दस्तों से अछूती हो। जीन्द जिले में तो यह स्थिति और ज्यादा विषम है, जैसे कि भाजपा सरकार जिले के लोगों से भाजपा का समर्थन न करने का बदला ले रही हो।

बिजली के अघोषित कट, हर रोज के जीवन की क्रूर वास्तविकता हैं। जींद जिला के गांवों में बिजली मात्र 8 से 10 घंटे ही मिल पाती है तथा गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। शहरों में 6 से 8 घंटों के अघोषित बिजली कट हैं। बिजली की वोल्टेज़ फ्लक्चुएशन तथा बार बार बिजली आने जाने के कारण न केवल घोर असुविधा होती है, परंतु आए दिन टेलीविज़न/फ्रिज/कंप्यूटर/बिजली से चलने वाली अन्य वस्तुएं या जल जाती हैं या खराब हो रही हैं।

बिजली की दरों में क्रूर वृद्धि ने आम जनमानस की कमर को तोड़ दिया है।

हरियाणा में मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। 10 साल के इस अरसे में विषम महंगाई व बढ़ती कीमतों के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बिजली की दरें न के बराबर बढ़ाईं, जैसा कि निम्नलिखित चार्ट से स्पष्ट है :–

श्रेणी	**बिजली की दरें मार्च 2005 में (कांग्रेस शासन से पहले)**	**बिजली की दर अक्टूबर 2014 में (जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा)**	**बिजली दरों में 10 वर्षों में बढ़ोत्तरी**
घरेलू बिजली	0–40 यूनिट – रुपया 2.63	0–40 यूनिट – रुपया 2.70	0–40 यूनिट – 7 पैसे की बढ़ोत्तरी
	41–300 यूनिट– रुपया 3.75	41–250 यूनिट– रुपया 4.50	41–250 यूनिट– 75 पैसे की बढ़ोत्तरी
	301–500 यूनिट – रुपया 4.55	251–500 यूनिट – रुपया 5.25	251–500 यूनिट – 70 पैसे की बढ़ोत्तरी
	501 से अधिक यूनिट– रुपया 4.90	501– 800 यूनिट – रुपया 5. 98	रुपया 1.08 की बढ़ोत्तरी

जैसा उपरोक्त तालिका से नजर आता है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बहुत ही कम बढ़ोत्तरी, यानि कि 10 साल में 7 पैसे प्रति यूनिट थी (0–40 यूनिट) और अधिक से अधिक बढ़ोत्तरी रुपया 1.08 प्रति यूनिट थी (यानि कि लगभग 10 पैसा प्रतिवर्ष)। बिजली की दरें भी बिजली की खपत के

आधार पर निर्धारित की जाती थीं। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा में 75 प्रतिशत तक घरेलू उपभोक्ता तो 0–800 यूनिट तक की श्रेणी में ही आ जाते हैं।

बिजली की दरें भी खपत के आधार पर बढ़ती थीं। बिजली की दरें निर्धारित करने का फॉर्मूला **'टेलीस्कोपिक टैरिफ'** था। यानि कि उपभोक्ता ने अगर 500 यूनिट बिजली भी इस्तेमाल की, तो उसकी बिजली की दर अलग अलग **स्लैब प्रणाली** में निर्धारित की जाएगी। पहले 40 यूनिट की दर 2.70 रुपये प्रति यूनिट होगी। 41 से 250 यूनिट की दर 4.50 रुपये प्रति यूनिट से लगाई जाएगी। 251 से 500 यूनिट की दर 5.25 रुपये के हिसाब से लगाई जाएगी। इस प्रकार बिजली की दरें स्लैब प्रणाली के अनुसार निर्धारित की जाती थीं।

दुर्भाग्यवश आपके नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को उल्टा कर नए **तुगलकी फरमान** बिजली की दरों बारे जारी कर दिए हैं। बीजेपी सरकार के कार्यकाल को अभी 15 माह ही हुए हैं और बिजली की अप्रत्याशित दरों का बोझ आपने जनता के सिर डाल दिया है। आज हरियाणा प्रांत में घरेलू बिजली दरों को तुगलकी फरमान जारी करते हुए 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

श्रेणी 1

श्रेणी	**आज की बिजली की दरें**
घरेलू बिजली	0–50 यूनिट – रुपये 2.70 प्रति यूनिट
	51–100 यूनिट– रुपये 4.50 प्रति यूनिट

श्रेणी 2

श्रेणी	**आज की बिजली की दरें**
घरेलू बिजली	0– 250 यूनिट – रुपया 5.00 प्रति यूनिट
	251–500 यूनिट– रुपया 6.05 प्रति यूनिट

इस प्रकार 250 यूनिट तक बिजली की खपत वाले उपभोक्ता पर बीजेपी सरकार ने मात्र 15 महीने में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी है। 250 से 500 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ता पर बीजेपी सरकार ने मात्र 15 महीने में 80 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डाल दिया है।

श्रेणी 3

श्रेणी	**आज की बिजली की दरें**
घरेलू बिजली	500 यूनिट से अधिक – रुपया 6.75 प्रति यूनिट

इस प्रकार बीजेपी सरकार ने मात्र 15 महीने में 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत वाले उपभोक्ता पर 70 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।

सबसे ज्यादा अन्याय की बात बीजेपी सरकार द्वारा यह की गई है कि टेलीस्कोपिक टैरिफ को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानि कि अगर कोई उपभोक्ता 501 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेगा, तो उसे सभी 501 यूनिट बिजली के लिए 6.75 रुपये प्रति यूनिट की लागत देनी पड़ेगी। जबकि पहले यह राशि स्लैब प्रणाली के अनुरूप दी जाती थी और निचली स्लैब्स की बिजली खपत की दर उस स्लैब के रेट के अनुसार निर्धारित की जाती थी।

फ्यूल सरचार्ज तथा म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पर भाजपा सरकार रुपये 1.72 प्रति यूनिट की अतिरिक्त वसूली कर रही है, जो सरासर अप्रासंगिक है।

<u>वाणिज्यिक संस्थानों तथा उद्योगों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है।</u> वाणिज्यिक संस्थानों यानि दुकानों, चक्की आदि के लिए कांग्रेस सरकार में केवल बिजली की खपत के ही पैसे लिए जाते थे। छोटे उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम शुल्क नहीं था। भाजपा सरकार ने इस श्रेणी में भी 5 किलोवाट तक बिजली की दरें रुपये 5.85 से बढ़ाकर रुपये 6.05 कर दी यानि कि हर साधारण व्यापारी की दुकान के बिल में 20 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की। 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक की दरें भी रुपये 6.10 से बढ़ाकर रुपये 6.75 कर दीं यानि कि मध्यम दर्जे के सभी दुकानों तथा वाणिज्यिक संस्थानों में बीजेपी द्वारा 65 पैसा प्रति यूनिट दरों में इजाफा कर दिया गया। लगभग यही स्थिति लघु उद्योगों की भी है।

महोदय, बीजेपी सरकार के 15 माह के कार्यकाल ने हरियाणा के निवासियों क जीवन दूभर कर दिया है। इस विरोध ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उपरोक्त मुद्दों पर सरकार अपना रवैया बदले व ठोस कदम उठाए वर्ना आपकी सरकार हरियाणा के साधारण जनमानुष के रोष से बच नहीं पाएगी।

निवेदक,

(रणदीप सिंह सुरजेवाला)

विधायक तथा मीडिया इंचार्ज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी